मुख्यमंत्री भजनलाल ने लोकदेवता बाबा रामदेव मंदिर के दर्शन किये

उन्होंने एक किलोमीटर पैदल यात्रा के बाद मैगा आई स्क्रीनिंग कैंप का उद्घाटन किया

जैसलमेर/पोकरण, 31 जुलाई (नि.सं.)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गुरुवार को बाबा रामदेव की नगरी रामदेवरा पहुंचे। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले बाबा रामदेव पैनोरमा का दौरा किया। इसके बाद, वे पैनोरमा से रामदेवरा मंदिर तक पैदल चल कर बाबा रामदेव के दर्शन करने पहुंचे। इस दौरान सीएम ने मेगा आई स्क्रीनिंग कैंप का उद्घाटन किया।

भजनलाल शर्मा हाथ में ध्वजा लिए पैनोरमा से करीब एक किलोमीटर की पैदल यात्रा करके बाबा रामदेव के समाधि परिसर पहुंचे। यहां उन्होंने लगभग 20 मिनट तक पूजा-अर्चना की।

उन्होंने कहा कि लोक देवता बाबा रामदेव की पुण्यभूमि पर पहली बार ऐतिहासिक नेत्र-कुंभ का आयोजन हो रहा है। मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे यहां आने का अवसर प्राप्त हुआ।

उन्होंने कहा, पोकरण, जैसलमेर, बाड़मेर और फलोदी की पहचान विश्व स्तर पर पर्यटन के क्षेत्र में रही है। बाबा रामदेव ने इस पावन भूमि पर जन्म लेकर सामाजिक समरसता की स्थापना की थी। इस नेत्र-कुंभ में, मेले में आने वाले लगभग सवा लाख लोगों की निशुल्क नेत्र जाँच की जाएगी। ये कैंप सक्षम संस्था की ओर से लगाया जा रहा है। सक्षम संस्था के राष्ट्रीय संगठन मंत्री चंद्रशेखर ने बताया कि रुचिचा धाम में 33 दिनों तक चलने वाले इस नेत्र-कुंभ में मरीजों की आंखों की जांच की जाएगी।

■ सक्षम संस्था द्वारा लगाया जा रहा नेत्र कुंभ 33 दिन चलेगा। इसमें मरीजों को चश्मा, दवाई तथा इलाज निशुल्क किया जायेगा।

रुणिचा धाम परिसर में लगभग 1 एकड़ भूमि पर अस्थायी अस्पताल तैयार किया गया है। यहां आधुनिक चिकित्सा उपकरणों और विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम मौजूद रहेगी। कमजोर नज़र वाले लोगों को चश्मा दिया जाएगा। फ्री दवाइयां दी जायेंगी, तथा गंभीर मरीजों का कैंप में ही इलाज भी होगा।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को रामदेवरा में लोकदेवता बाबा रामदेव के दर्शन किये। उन्होंने हाथ में ध्वजा लेकर पैनोरमा से बाबा रामदेव के समाधि परिसर तक पैदल यात्रा की।

महेश जोशी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

साक्ष्य नहीं है और परिवादी यह राशि कहां से लाया, उसका भी उल्लेख नहीं है। इसके अलावा, ईडी अपनी रिपोर्ट में जोशी के बेटे की फर्म में 50 लाख रुपए का लेनदेन बता रही है। यह राशि बेटे की कंपनी ने लोन के तौर पर ली थी और उसे लौटाया भी जा चुका है। वहीं, इस राशि को लेकर सिविल केस भी लंबित चल रहा है।

ईडी कोर्ट ने गत दिनों जोशी को जमानत देने से इनकार कर दिया था और उसके बाद ईडी ने जोशी तथा उनके बेटे रोहित सहित, डेढ दर्जन आरोपियों के खिलाफ ईडी कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया था। इस दौरान, जोशी की पत्नी का निधन होने पर कोर्ट ने उन्हें दो बार अंतरिम जमानत का लाभ दिया था।

अमेरिका-चीन-पाकिस्तान गठबंधन भारत के लिए खतरनाक - खड़गे

खड़गे ने सवाल किया कि क्या प्रधानमंत्री भारत पर लगाये ट्रंप के बेबुनियाद आरोपों पर भी चुप रहेंगे

नयी दिल्ली, 31 जुलाई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के बयानों पर चुप्पी साधने वाले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को समझ लेना चाहिए कि भारत के खिलाफ अमेरिका पाकिस्तान तथा चीन का गठजोड़ बन रहा है और यह अत्यंत खतरनाक है।

खरगे ने कहा कि सैन्य कार्रवाई रोकने को लेकर ट्रंप के बयानों पर मोदी ने संसद में मौन व्रत धारण कर रखा था।

सवाल है कि अब ट्रंप ने भारत पर जो बेबुनियाद आरोप लगाए हैं, क्या उस पर भी प्रधानमंत्री चुप रहेंगे।

उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने आयात शुल्क की जो वजह बताई है कि वह चौंकाने वाली है। आयात शुल्क लगाने की वजह उन्होंने भारत द्वारा रूस से तेल आयात, भारत द्वारा रूस से हथियारों की खरीद, भारत का ब्रिक्स का सदस्य होना, ब्रिक्स का अमेरिकी डॉलर पर हमला बताया है। ये भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता वाली राष्ट्रीय नीति पर कड़ा प्रहार है।

खरगे ने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार में डॉ. मनमोहन सिंह ने अमेरिका सहित 45 देशों से परमाणु छूट दिलाई थी।

'मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया'

राहुल गांधी ने संसद भवन परिसर में पत्रकारों से बातचीतष करते हुये सरकार पर तीखा हमला बोला

नयी दिल्ली, 31 जुलाई। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि आज सबसे बड़ी समस्या देश की आर्थिक नीति, रक्षा नीति और विदेश नीति की है जिसे मोदी सरकार ने बर्बाद कर दिया है।

गांधी ने संसद भवन परिसर में गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुये सरकार पर तीखा हमला करते हुये कहा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की आर्थिक नीतियां पूरी तरह विफल हो गई है और उसने देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया है। भारतीय अर्थव्यवस्था मर चुकी है। मोदी ने इसे खत्म कर दिया है। इस राज में अडानी-मोदी साझेदारी, नोटबंदी और त्रुटिपूर्ण जीएसटी, असफल असेम्बल इन इंडिया, एमएसएमई का सफाया, किसान कुचले गए हैं। मोदी ने भारत के युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया है क्योंकि नौकरियाँ नहीं हैं।

■ गांधी ने कहा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की आर्थिक नीतियां पूरी तरह विफल हो गई हैं और उसने देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया है। भारतीय अर्थव्यवस्था मर चुकी है। मोदी ने इसे खत्म कर दिया है।

उन्होंने कहा कि आज देश की सबसे बड़ी समस्या देश की आर्थिक नीति, रक्षा नीति और विदेश नीति है जिसे मोदी सरकार ने बर्बाद कर दिया है। मोदी इस देश को बर्बाद कर रहे हैं। वह सिर्फ एक ही व्यक्ति अडानी के लिए काम करते हैं। इन लोगों ने सारे के सारे छोटे कारोबार खत्म कर दिए हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था आज एक मृत अर्थव्यवस्था बन गयी है। उन्होंने एक अन्य सवाल पर कहा भारत एक मृत अर्थव्यवस्था है, क्या आप लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। पूरी दुनिया जानती है- भारत की इकॉनामी डेड इकानामी है और भाजपा ने देश की इकॉनामी को खत्म किया है। क्यों खत्म किया है- अडानी की मदद करने को खत्म किया है। विदेश मंत्री भाषण देते हुए कहते हैं कि हमारी विदेश नीति बहुत ही शानदार है। एक तरफ अमेरिका, भारत को भला-बुरा कह रहा है तो दूसरी तरफ चीन हमारे पीछे पड़ा है। जब आप अपना डेलिगेशन दुनिया भर में भेजते हैं, तो कोई भी देश पाकिस्तान की निंदा नहीं करता। कांग्रेस नेता ने मोदी पर हमला करते हुये कहा कि ये देश को कैसे चला रहे हैं, इन्हें देश चलाना ही नहीं आता, पूरी तरह से भ्रमित हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषण में ट्रंप और चीन का नाम नहीं लेते। जिस पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने पहलगाम में हमला करवाया वह राष्ट्रपति ट्रंप के साथ लंच कर रहे हैं और हमारी सरकार कह रही है कि हमें बड़ी सफलता मिली है।

उन्होंने कहा आश्चर्य की बात यह है कि ट्रंप ने 30-32 बार कहा है कि उन्होंने दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई को रुकवाया है। उन्होंने यह भी कहा है कि पांच विमान गिरे हैं और अब वो 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने की बात बोल रहे हैं। बड़ा सवाल है कि मोदी इन सवालों का जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं।

अमेरिका पाकिस्तान का तेल भंडार विकसित करेगा

नयी दिल्ली, 31 जुलाई। भारत और रूस के बीच दशकों पुराने सहयोग और मित्रता से बुरी तरह चिढ़े हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प ने भारत पर 25 प्रतिशत आयात शुल्क और जुर्माना लगाने के बाद अब पाकिस्तान के तेल भंडार के विकास में सहयोग के लिए उसके साथ एक नया समझौता किया है।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर बुधवार रात पाकिस्तान के तेल भंडार विकास समझौते की घोषणा की। उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान से एक नये व्यापार ढ ांचे को अंतिम रूप दे दिया गया है। इसका मकसद पाकिस्तान के अप्रयुक्त तेल भंडार विकसित करना और आयात शुल्क घटाना है। इस काम के लिए अमेरिकी तेल कंपनी का चयन अभी नहीं हुआ है। यह कंपनी पाकिस्तान के 'विशाल तेल भंडार' के विकास का काम करेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने लिखा, हमने अभी-अभी पाकिस्तान के साथ एक समझौता किया है, जिसके तहत पाकिस्तान और अमेरिका अपने विशाल तेल भंडार को विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे।

■ ट्रंप ने कहा, मुझे परवाह नहीं है कि भारत-रूस के साथ क्या करता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दोनों मिल कर अपनी मृत अर्थव्यवस्थाओं को डुबा दें।

क्या दिल्ली व वॉशिंगटन एक...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ऊर्जा और रक्षा संबंधों का गहराना और ब्रिक्स में उसकी मुखर भूमिका, इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिकी प्रभुत्व के लिए खतरा है। लेकिन भारत को टैरिफ से सज़ा देने की इस कोशिश में ट्रंप उस व्यापक रणनीतिक ढांचे की अनदेखी कर रहे हैं, जिसे बुश, ओबामा और बाइडन जैसे पूर्व राष्ट्रपतियों ने मिलकर तैयार किया था तथा जिसमें भारत को चीन के मुकाबले एक अहम संतुलन और लोकतांत्रिक साझेदार के रूप में देखा गया था।

रैंड कॉर्पोरेशन के डेरेक जे. ग्रॉसमैन ने 31 जुलाई 2025 को भारत-अमेरिका संबंधों का 1998 के बाद का सबसे बुरा दिन बताया। उनका कहना है कि लेन-देन आधारित, आवेगपूर्ण और सार्वजनिक रूप से टकराव करने वाली ट्रम्प की शैली ने इस पारंपरिक रूप से स्थिर रिश्ते को झकझोर दिया है। नवरूप सिंह ने ट्वीट किया कि 25 वर्षों की प्रगति पल भर में मिटा दी गई। यह बात, ट्वीट की गई कई अन्य विश्लेषकों की उस भावना को व्यक्त करती है, जिसमें ट्रंप की नाराज़गी के पीछे अमेरिका की विदेश नीति में भारत को लेकर सोच में बदलाव की आशंका नज़र आती है।

दक्षिण एशिया मामलों के विशेषज्ञ माइकल कुगेलमैन कहते हैं कि भारत ने ट्रंप के दूसरे कार्यकाल से मज़बूत रिश्ते की उम्मीद की थी, खासकर पहले कार्यकाल की दोस्ताना टोन के बाद। लेकिन शायद भारत ट्रंप की अनिश्चित विदेश नीति को लेकर सतर्क नहीं रहा। कृषि उत्पादों, डिजिटल टैक्स और दवाओं की कीमतों को लेकर भारत के अनमने रुख ने ट्रंप की उस लंबे समय से चली आ रही शिकायत को और हवा दी, कि व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में है, हालाँकि हाल के वर्षों में यह अंतर कम हुआ है।

यह टैरिफ एक दोतरफा ट्रेड वॉर को जन्म दे सकता है, जिसमें भारत भी जवाबी टैरिफ या रक्षा सौदों और महत्वपूर्ण खनिजों से जुड़े समझौतों को धीमा कर सकता है। लेकिन नुकसान केवल व्यापार तक सीमित नहीं रहेगा। दांव पर है भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी की पूरी संरचना, मालाबार जैसे संयुक्त नौसैनिक अभ्यासों से लेकर सेमीकंडक्टर, साइबर सुरक्षा और उन्नत तकनीक में सहयोग तक। ट्रंप द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था को मृत कहे जाने वाली टिप्पणी दिल्ली में कड़वाहट ही पैदा करेगी, जहाँ मोदी सरकार अमेरिका से निवेश आकर्षित करने और भारत को भरोसेमंद वैश्विक साझेदार दिखाने की कोशिश में लगी है।

इसके अलावा, यह कदम भारत को चीन और रूस के करीब ले जा सकता है, विशेषकर ब्रिक्स, एससीओ और ग्लोबल साउथ जैसे बहुपक्षीय मंचों में। वर्षों से भारत ने मॉस्को के साथ अपने पारंपरिक संबंधों और वाशिंगटन के साथ अपने बढ़ते सहयोग के बीच संतुलन बनाए रखा है। ट्रंप की यह कार्रवाई उस संतुलन को डगमगाने का जोखिम पैदा कर रही है।

अब, जबकि अगस्त के अंत में वार्ता का एक और दौर निर्धारित है, देखना यह होगा कि क्या कूटनीति इस रिश्ते को बचा सकती है। भारत ऐसी धमकियों के आगे झुकने वाला नहीं दिखता। नई दिल्ली एकतरफा समझौतों का लगातार विरोध करती रही है और 2026 के आम चुनावों को देखते हुए घरेलू राजनीतिक दबाव के चलते किसी भी प्रकार की ढील की संभावना कम है।

इस तरह, ट्रंप की टैरिफ नीति ने न केवल आर्थिक रिश्तों को खतरे में डाला है, बल्कि उस व्यापक रणनीतिक साझेदारी को भी संकट में डाल दिया है, जो 21वीं सदी की भू-राजनीति की नींव बन गई थी। अगर यह सिलसिला यूँ ही चलता रहा, तो दोनों देशों के दशकों के द्विदलीय (बाय पार्टिसन) प्रयास मिट्टी में मिल सकते हैं, जो आपसी सम्मान, रणनीतिक समन्वय और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित संबंध बनाने के लिए किए गए थे। अब सवाल केवल टैरिफ का नहीं है, बल्कि यह है कि क्या वाशिंगटन और नई दिल्ली समय रहते भरोसे को फिर से स्थापित कर सकते हैं?

राहुल 15 दिन की ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बातचीत करेंगे, जिन्हें मतदाता सूची से बाहर कर दिया गया है। विपक्षी नेता इस दौरान चुनाव आयोग और सत्तारूढ दल पर बड़ा हमला बोलेंगे। बिहार एसआईआर का मुद्दा संसद से लेकर बिहार की सड़कों तक गूंजता रहेगा, क्योंकि चुनाव आयोग जनता के जनादेश को छीनने का काम कर रहा है। बिहार में अगर मोदी एंड कम्पनी को हार का सामना करना पड़ा, तो यह उनकी राजनीति के लिए बड़ा झटका होगा।

मोदी पहले से ही कई मोर्चों पर मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, लेकिन, जैसा कि एक वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा, वे किसी भी कीमत पर बिहार की हार बर्दाश्त नहीं कर सकते।

'राहुल गांधी जनता को बेवकूफ बनाने बिहार आते हैं'

मुजफ्फरपुर, 31 जुलाई। जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने अपनी बिहार बदलाव यात्रा के दौरान मुजफ्फरपुर के सरैया में कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी लोगो को बेवकूफ बनाने के लिए बिहार आते हैं।

कुमार ने गांधी के आगामी बिहार दौरे और पदयात्रा पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अब बिहार की जनता को देखना है कि वो चुनाव से पहले बिहार घूमने आ रहे हैं या उनकी मनसा बेवकूफ बनाकर वोट लेने की हैं। उन्होंने कहा कि जब बिहार के बेरोजगार बच्चे दर-दर भटक रहे थे, तब वो कहां थे, जब कोविड में लोग पैदल चलकर दिल्ली-मुंबई से बिहार आ रहे थे तब उन्होंने बिहार के लोगों की कितनी मदद की। जनसुराज के नेता ने कहा कि राहुल गांधी बतायें कि बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए, बेरोजगारी हटाने के लिए उन्होंने कौन सा प्रयास किया।

किशोर ने कहा कि पिछले 40-45 साल से बिहार में उन्ही पार्टियों का राज रहा है जो वोट मांगने जनता के बीच उतर रही हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों ने मिल कर बिहार को मजदूरों की फैक्ट्री बना दिया है। उन्होंने कहा कि इस बार लोग ऐसी पार्टियों के झांसे में नहीं आने वाले हैं और जनता जनसुराज के पक्ष में मतदान का मन बना चुकी है।

'तेलंगाना विधायकों की आयोग्यता विवाद पर वि.स. अध्यक्ष 3 महीने में फैसला करें'

सुप्रीम कोर्ट ने बीआरएस के 10 विधायकों के खिलाफ लंबित अयोग्यता याचिकाओं पर राज्य विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश दिया

नयी दिल्ली, 31 जुलाई। उच्चतम न्यायालय ने तेलंगाना सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के 10 विधायकों के खिलाफ लंबित अयोग्यता याचिकाओं पर तीन महीने में निर्णय लेने का राज्य विधानसभा अध्यक्ष को गुरुवार को निर्देश दिया।

मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई और न्यायमूर्ति ए जी मसीह की पीठ यह निर्देश देते हुए कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस मुद्दे पर उनकी नोटिस के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सात महीने बाद ही संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया।

■ मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई और न्यायमूर्ति ए जी मसीह की पीठ ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस मुद्दे पर उनके नोटिस के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सात महीने बाद ही संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया।

शीर्ष अदालत ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि विधायक सुनवाई में शामिल होने में किसी तरह से कोई भी टालमटोल करते हैं, तो उनके खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जा सकता है।

न्यायमूर्ति गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि संसद को विधायकों की अयोग्यता की वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा करनी चाहिए क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा करने वाले दलबदलुओं के खिलाफ कार्रवाई को विफल करने के लिए ऐसी कार्यवाही (सुनवाई और फैसला) में अत्यधिक देरी करते हैं।

पीठ ने तेलंगाना उच्च न्यायालय की खंडपीठ के 22 नवंबर, 2024 के फैसले के खिलाफ दायर बीआरएस नेता पाडी कौशिक रेड्डी और के टी रामा राव की अपील को स्वीकार कर लिया।

शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय की खंडपीठ के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें अध्यक्ष को चार हफ्तों के भीतर सुनवाई के लिए तारीखें तय करने के एकल पीठ के निर्देश को रद्द कर दिया गया था।

दोनों बीआरएस नेताओं की याचिका में सत्तारूढ़ कांग्रेस में शामिल होने वाले 10 विधायकों के खिलाफ लंबित अयोग्यता कार्यवाही पर तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष द्वारा समय पर कार्रवाई करने की मांग की गई थी। शीर्ष अदालत ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता कार्यवाही में निर्णायक भूमिका में कार्य करते हैं। इस भूमिका विधानसभा अध्यक्ष उच्च न्यायालय और शीर्ष न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन एक न्यायाधिकरण के रूप में भी कार्य करते हैं। पीठ ने स्पष्ट किया कि विधानसभा अध्यक्ष को ऐसे मामलों में कोई संवैधानिक छूट प्राप्त नहीं है।

शीर्ष अदालत ने यह तथ्य पर गौर करते हुए कि राजनीतिक दलबदल राष्ट्रीय चर्चा का विषय रहा है और अगर इसे रोका नहीं गया तो यह लोकतंत्र के लिए बाधा बन सकता है।

जिस जूनून से अमेरिका ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ये सभी नई संधियाँ और समायोजन अमेरिका के राष्ट्रपति की उस हताशा से जन्मे हैं, जो उन्होंने खुद को वैश्विक मामलों का निर्णायक नेता स्थापित करने के प्रयास में दिखाई है। वे व्लादिमीर पुतिन के साथ अपने 'व्यक्तिगत करिश्मा' के ज़रिए यूक्रेन संकट सुलझाने की उम्मीद कर रहे थे, जिसमें वे पूरी तरह विफल रहे।

वे इज़रायल के नेता बेंजामिन नेतन्याहू के साथ भी कोई सफलता नहीं पा सके। गाज़ा में जारी मानवीय संकट को रोकने के उनके प्रयास बार-बार विफल रहे। नेतन्याहू ने गाज़ा और सीरिया पर हमलों में बार-बार अमेरिकी राष्ट्रपति की उपेक्षा की।

विदेश नीति में ट्रम्प की असफलता उनके पूर्ववर्ती की तरह ही सामने आई है, जिनकी उन्होंने तीव्र आलोचना की थी। अब वही कलंक खुद ट्रम्प पर चिपक गया है।

इस पृष्ठभूमि में, जब ट्रम्प की "डील मेकर" की छवि पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है, ट्रंप ने यूरोपीय संघ, जापान और ब्रिटेन के साथ व्यापार एजेंडे को आगे बढ़ ाया। इसी तरह, उन्होंने भारत के साथ भी एकतरफा व्यापार समझौता करने की कोशिश की, लेकिन भारत ने झुकने से इनकार कर दिया।

भारत को सजा देने की ट्रम्प की उग्रता उनकी अधीरता को दर्शाती है। उन्होंने बार-बार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ अपनी 'दोस्ती' का दावा किया है, लेकिन अब वे भारत और मोदी दोनों को एक कठिन वार्ताकार मानते हैं, जिनसे वे निराश हैं।

ट्रंप ने भारत पर अधिक टैरिफ लगा दिए, जबकि व्यापार वार्ता अभी समाप्त नहीं हुई थी। अब वे रूसी कच्चे तेल की भारतीय खरीद पर और अधिक टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं, जो अभी घोषित नहीं हुए हैं। खास बात यह है कि उन्होंने चीन पर ऐसा कोई टैरिफ नहीं लगाया है, जबकि वह भी रूस से भारी मात्रा में तेल खरीद रहा है।

इससे भारत एक दोहरे संकट में फंस गया है। अमेरिका और भारत के बीच सहयोग की अपेक्षा थी, लेकिन अब वे विरोधी पक्षों में खड़े दिख रहे हैं।

इस बीच, असली लाभार्थी चीन बन रहा है। अंतरराष्ट्रीय मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार, चीन पहले से ही अमेरिका के साथ एक समझौते पर बातचीत कर रहा है और यह वार्ता स्टॉकहोम में प्रगति पर है। अगर यह सौदा हो जाता है, तो अमेरिका अपनी निगाहें भारत जैसे अन्य देशों पर केन्द्रित कर सकता है।

विपक्ष ने दिन ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

के बाद, शून्यकाल शुरु करते हुए सदन की कार्यवाही प्रारंभ की, लेकिन विपक्षी दलों के सदस्य हंगामा और नारेबाजी करते हुए सदन के बीचोंबीच आ गये। हंगामा बढ़ने लगा तो बिरला ने सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी।

अविप्रा

अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

टोडरमल मार्ग, सिविल लाइन्स, अजमेर राजस्थान 305001

Email : ajmerada@gmail.com फोन नं. 0145-2620740, 0145-2627748

अजमेर महानगर की ओर अग्रसर

अजमेर के समग्र विकास में अजमेर विकास प्राधिकरण हर कदम पर अग्रणी

प्रगतिरत विकास कार्य

क्र.सं.	मद	कार्य	राशि (रु. करोड़ों में)
1.	योजना	48	164.20
2.	गैर योजना	43	98.46
3.	डिपोजिट	13	273.10
	योग	104	535.76 करोड़

तीन नई आवासीय/व्यावसायिक योजनाएं

अटल आवासीय योजना : चाचियावास में 39 बीघा (28485.44 वर्गमीटर) में 191 भूखंडों की अटल आवासीय योजना ।

तोलामाल ट्रांसपोर्ट हब योजना (किशनगढ़): नसीराबाद बाईपास पर तोलामाल में 514 बीघा में बहुउद्देशीय ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक हब योजना।

पृथ्वीराज नगर व्यावसायिक ब्लॉक: पृथ्वीराज नगर में 3 बहुउद्देशीय व्यावसायिक ब्लॉक में भूखंडों की नीलामी भी जारी है।

प्राधिकरण की योजनाएं

पृथ्वीराज नगर, हरिभाऊ उपाध्याय नगर (मुख्य), हरिभाऊ उपाध्याय नगर विस्तार, डी.डी. पुरम, जे.पी. नगर, सूरजकुण्ड, अटल आवासीय, तोलामाल, कोटडा, पंचशील नगर, अर्जुनलाल सेठी नगर, चन्दरवरदायी नगर।

अटल आवासीय योजना

चाचियावास स्थित अटल आवासीय योजना में 191 भूखण्डों की ऑनलाईन लॉटरी से आवंटन किया जाएगा। भूखण्ड हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है। आवेदन करने की अंतिम दिनांक 12.08.2025 रखी गई है। योजना में भूखण्डों की आरक्षित दर 16227/- रुपए प्रति वर्गमीटर अर्थात 13568/- रुपए प्रति वर्गगज रखी गई है।

योजना क्षेत्र में विकास कार्य (करोड़ो में)

1.	सड़क	64.37
2.	पेयजल	50.53
3.	विद्युत	8.63
4.	ड्रेनेज	9.72
5	अन्य	30.95
	योग	164.20

गैर योजना क्षेत्र में विकास कार्य (करोड़ों में)

1.	सड़क	42.33
2.	विद्युत	11.15
3.	ड्रेनेज	28.00
4.	अन्य	16.98
	योग	98.46

अन्य आकर्षण

1. भूखण्डों की नीलामी पूर्ण पारदर्शिता से यू.डी.एच पोर्टल के माध्यम से
2. ऑनलाइन सेवा प्रदायगी व्यवस्था
3. आमजन से फीड बैक लेकर समस्याओं के निवारण हेतु हैल्प डेस्क
4. हरियालो राजस्थान (एक पेड मां के नाम) के अन्तर्गत 1 लाख पोधारोपण
5. राइजिंग राजस्थान के अन्तर्गत 76 एमओयू में 2300 करोड का निवेश
6. क्षेत्र के सर्वांगीण विकास की ओर अग्रसर